Asian Culture
B.A. Semester II
Paper I : South Asia (1870-1919)

Department of Western History
University of Lucknow

*(Course Instructor: **Prof. Abha Trivedi**)*

Reforms of Lord Ripon (1880-1884) :

- Lord Ripon was a member of William Gladstone's council and a Liberal.
- He wrote "The Duty of the Age" in 1852.
- Being a Liberal, his policies were somehow just opposite to Lytton's.
- He passed The Factory Act in 1881 for betterment of Factory and mill Workers. It was only implemented on those factories where at least 100 labourers had been working since last 4 months.
- Under this Act it was decided that no child under the age of 7, shall work. The working hours (9 hours) were decided for the children between age of 7 and 12. Fencing was mandatory around heavy machines. A break of 1 hour was mandatory per day, and 4 day-holiday was mandatory in a month.I
- Any Factory owner who didn't follow these rules, were subjected to a penalty of 200rs.
- Ripon also proposed Indian Immigration Bill in 1882.
- First Complete Census was taken in 1881.
- The state of Mysore was restored to Wadiyaar Rulers under the Rendition Act of 1881.
- Lord Ripon repealed the Vernacular Press Act in 1882.
- Lord Ripon continued the policy of Economic Decentralization. In 1882, He divided the sources of Revenue into 3 categories- Imperial, Provincial and Divided.
- He appointed Hunter Commission under the chairmanship of Sir William Hunter, who was a member of Viceroy's Executive Council. This commission was appointed to evaluate the progress of Education (which was supposed to be executed under Wood's Despatch).
- The commission's recommendations were about :
    1. Academic Education- so students could be prepared for the Entrance examination.

2. Commercial and Avocational Education- so students could be prepared for jobs and commercial career.

- This Commission was only appointed to give recommendations for Primary and Secondary Education. University Level Education was not concerned under this reform.
- Lord Ripon passed a Resolution on Local Self-Government in 1882. In rural areas, Local Boards were appointed and in Urban Areas, Municipal Corporations were appointed. He made sure that official intervention should be least.
- In 1883, Dispute on Ilbert Bill was raised. Sir Courtenay Peregrine Ilbert was the Law-member of Viceroy's Executive Council, and he proposed this Bill.
- This Bill was against the policy of Apartheid. This Bill could not make its demands, and with some amendments, it was passed on 26 January 1884.
- The Amended bill stated that, A jury (7 members must be European or American out of 12 total members) was required if an Indian judge was to face a European Convict.

लॉर्ड रिपन के सुधार (1880-1884):

- लॉर्ड रिपन, विलियम ग्लैडस्टोन की परिषद के उदारवादी सदस्य थे।
- उन्होंने 1852 में "द ड्यूटी ऑफ़ द एज" लिखा था।
- उदारवादी होने के नाते, उनकी नीतियां लिटन की नीतियों के विपरीत थीं।
- उन्होंने फ़ैक्टरी और मिल मजदूरों की बेहतरी के लिए 1881 में फ़ैक्टरी एक्ट पास किया। यह केवल उन कारखानों पर लागू किया गया था जहां पिछले 4 महीनों से कम से कम 100 मजदूर काम कर रहे थे।
- इस अधिनियम के तहत यह निर्णय लिया गया कि 7 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा काम नहीं करेगा। 7 से 12 साल के बच्चों के लिए काम के घंटे (9 घंटे) तय किए गए थे। भारी मशीनों के आसपास बाड़ लगाना अनिवार्य था। प्रति दिन 1 घंटे का ब्रेक अनिवार्य था, और एक महीने में 4 दिन की छुट्टी अनिवार्य थी।
- जो भी फैक्ट्री मालिक इन नियमों का पालन नहीं करते थे, उन पर 200 रुपयों का जुर्माना लगाया जाता था।
- रिपन ने 1882 में भारतीय आप्रवासन विधेयक का भी प्रस्ताव रखा।
- 1881 में पहली पूर्ण जनगणना की गई।
- 1881 के संशोधन अधिनियम के तहत मैसूर राज्य को वाडियार शासकों को बहाल किया गया था।
- लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया।
- लॉर्ड रिपन ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति जारी रखी। 1882 में, उन्होंने राजस्व के स्रोतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया-साम्राज्यवादी, प्रांतीय और विभाजित।

- उन्होंने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग की नियुक्ति की, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। यह आयोग शिक्षा की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त किया गया था (जिसे वुड्स डिस्पैच के तहत निष्पादित किया जाना था)।

आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित थीं:

1. शैक्षणिक शिक्षा- ताकि छात्रों को प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार किया जा सके।
2. वाणिज्यिक और व्यावसायिक शिक्षा- ताकि छात्रों को नौकरी और जीविकोपार्जन के लिए तैयार किया जा सके।

- यह आयोग केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए सिफारिशें देने के लिए नियुक्त किया गया था। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इस सुधार के तहत नहीं थी।
- लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन पर एक प्रस्ताव पारित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में, स्थानीय बोर्ड नियुक्त किए गए और शहरी क्षेत्रों में, नगर निगम नियुक्त किए गए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि आधिकारिक हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए।
- 1883 में, इल्बर्ट बिल पर विवाद उठाया गया था। सर कोर्टनी पेरेग्रीन इलबर्ट वायसराय की कार्यकारी परिषद के कानून-सदस्य थे, और उन्होंने इस विधेयक का प्रस्ताव रखा।
- यह विधेयक रंगभेद की नीति के विरुद्ध था। यह विधेयक अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ और कुछ संशोधनों के साथ 26 जनवरी 1884 को इसे पारित कर दिया गया।
- संशोधित विधेयक में कहा गया कि, यदि किसी भारतीय जज को किसी यूरोपीय आरोपी का मुकदमा सुनना होता तो एक जूरी (12 सदस्यों में से 7 सदस्य यूरोपीय या अमेरिकी होने चाहिए), आवश्यक थी।